भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 433
21 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

मंगलुरु मत्स्य बंदरगाह

433. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के मंगलुरु मत्स्यन बंदरगाह पर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अवसंरचना संबंधी प्रावधानों की समीक्षा की है;

(ख) कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में वर्तमान योजनाओं, परियोजनाओं तथा लाभार्थियों की स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त मत्स्यन बंदरगाह के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है और इसमें केंद्रीय अंश, जारी की गई निधि, भौतिक प्रगति, लाभार्थियों तथा उससे प्राप्त परिणाम क्या रहे हैं;

(घ) अवसंरचना, सुरक्षा, बीज, ऋण, विपणन, जैव- सुरक्षा अथवा परिचालन संबंधी बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित घटकों को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई तथा उन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग , प्रत्यक्ष बैठकों, वर्चुअल बैठकों, क्षेत्र दौरों और योजना कार्यान्वयन के लिए समर्पित एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग ने वर्ष 2024 में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) के तहत 37.47 करोड़ रुपये की लागत से मंगलूरु फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 22.48 करोड़ रुपये है। भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक कर्नाटक राज्य में मत्स्यपालन विकास परियोजनाओं के लिए 126.01 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें फिशिंग हार्बर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित कोष भी शामिल है, जिसके अंतर्गत मंगलुरु फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना भी आती है। कर्नाटक राज्य सरकार ने मंगलुरु फिशिंग हार्बर परियोजना में 25% की वास्तविक प्रगति और 6.31 करोड़ रुपये के व्यय की रिपोर्ट दी है। इस परियोजना की परिकल्पना 1600 फिशिंग वेसल्स के लिए बर्थिंग की सुविधा प्रदान करने

और मत्स्यपालन क्षेत्र के लगभग 18000 मछुआरों और संबद्ध हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को लाभान्वित करने के लिए की गई थी। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि मंगलुरु फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना के लंबित घटकों को 21 मई, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग ने वर्ष 2020-21 से 2026-2027 तक कर्नाटक राज्य में कुल 1,053.60 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न मत्स्यपालन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमएमएसवाई के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट दी है कि कर्नाटक के तीन तटीय जिलों में 212 लाभार्थियों को लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों के तहत कवर किया गया है, जिसमें गहरे डीप-सी फिशिंग वेसल्स, आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इन्सुलेटेड वाहन, आइस बॉक्स के साथ तिपहिया वाहन (थ्री-व्हीलर्स) और आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिलें शामिल हैं।

भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग ने मत्स्यपालन क्षेत्र की इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत कई उपाय किए हैं। इनमें फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग केंद्रों का विकास और आधुनिकीकरण, कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ मछली रखरखाव सुविधाएं, मत्स्य परिवहन और विपणन (मार्केटिंग) इन्फ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच, जलीय जीव स्वास्थ्य और जैव-सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, बीमा कवरेज को बढ़ावा देना और मछुआरों की क्षमता निर्माण शामिल हैं।